

Dated: 09.09.2024

BSE Limited,
Department of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.
Script Code:- 531946

Sub: Information published in the Newspaper of the 34th Annual General Meeting as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

In pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the information published in one English language daily newspaper and in one daily newspaper in the language of the region where the registered office of the Company is situated, regarding the Notice of the 34th Annual General Meeting dated Monday, 30th September, 2024.

Kindly update the same on your records and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For and on behalf on
Chadha Papers Limited

Chadha Papers Limited



Whole Time Director

Amanbir Singh Sethi
Wholetime Director
DIN: 01015203
Address: CTC061 The Crest Park Drive,
DLF5, Gurugram, Haryana-122011

Encl: a/a

2 कंपनी समाचार

संक्षेप में

अदाणी समूह ने चीन में बनाई अनुषंगी कंपनी

अदाणी समूह ने आपूर्ति श्रृंखला समाधान और परियोजना प्रबंधन सेवाएं देने के लिए चीन में एक अनुषंगी कंपनी बनाई है। समूह ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ने कहा कि सिंगापुर स्थित उसकी अनुषंगी की अनुषंगी ने 2 सितंबर, 2024 को चीन के शांघाई में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अदाणी एनर्जी रिसोर्सेज (शांघाई) (एईआरसीएल) का गठन किया है। कंपनी ने एईआरसीएल का गठन आपूर्ति श्रृंखला समाधान और परियोजना प्रबंधन सेवाएं देने का व्यवसाय करने के लिए किया गया है। इस सहायक कंपनी को अदाणी ग्लोबल पीटीई (एजोपीटीई), सिंगापुर ने गठित किया है, जो अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की अनुषंगी की अनुषंगी कंपनी है। एईएल खनन, सड़क, हवाई अड्डे, डेटा सेंटर और जल अवसंरचना व्यवसाय से जुड़ी है।

स्पाइसजेट का हिस्सा बेच सकते हैं चेरमैन

स्पाइसजेट के प्रवर्तक और चेरमैन अजय सिंह कोष जुटाने के हालिया दौर में एयरलाइन में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी बेच सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह दौर सितंबर के अंत तक पूरा होने का अनुमान है। 'किफायती एयरलाइन वित्तीय चुनौतियों, कानूनी लड़ाइयों और विमानों को ठप करने सहित कई समस्याओं से जूझ रही है। कंपनी धन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिससे उसे विभिन्न दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी। एक सूत्र ने बताया कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहें तो सिंह एयरलाइन में 15 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच सकते हैं।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन को सता रही बिना बिके वाहनों की तादाद

फाड़ा करेगा ऋणदाताओं से बात

अंजलि सिंह मुंबई, 8 सितंबर

अनबिके यात्री वाहनों की तादाद चिंताजनक स्तर तक बढ़ जाने पर फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) अब बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से औपचारिक रूप से संपर्क करने की तैयारी में है। वह ऋणदाताओं से अनुरोध करेगा कि वे डीलरों को पैसा मुहैया कराते वक्त सावधानी बरतें।

इससे पहले डीलरों के संगठन ने सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर्स (सायम) को दो बार पत्र लिखा और बिना बिके वाहनों के बढ़ती तादाद को लेकर चिंता जताई। बैंकों से संपर्क इस लिहाज से खास है क्योंकि एसोसिएशन ने जोर दिया है कि बैंकों और एनबीएफसी की ज्यादा फंडिंग और बिना बिके वाहनों की संख्या बढ़ने से डीलरों के मुनाफे में गिरावट आ सकती है। अगस्त महीने में अनबिके वाहनों का 70 से 75 दिनों का स्टॉक था और इसका मूल्य 77,800 करोड़ रुपये था, जिससे देश भर में डीलरों पर वित्तीय दबाव पैदा हो गया।

फाडा के अध्यक्ष मनोष राज सिंघानिया ने वाहनों की खुदरा बिक्री वाले उद्योग को भीतर वित्तीय सावधानी की जरूरत पर जोर दिया। सिंघानिया ने कहा, 'हम सभी एनबीएफसी और बैंकों को यह



बैंक और एनबीएफसी से की जाएगी चर्चा

सुनिश्चित करने के लिए लिखेंगे कि डीलरों के स्टॉक के स्तर के आधार पर फंडिंग की जाए तथा ज्यादा फंडिंग न हो, खास तौर पर इसलिए भी कि त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि डीलरों की सहमति के बिना फंडिंग न की जाए, भले ही ओईएम ने अनुरोध किया हो, ताकि और ज्यादा स्टॉक इकट्ठा होने से बचा जा सके।

एसोसिएशन ने यह भी बताया कि किस तरह स्टॉक का अधिक स्तर डीलरों के लाभ को कम कर रहा है। डीलर आम तौर पर कम मार्जिन पर काम करते हैं जो औसतन तीन से चार प्रतिशत के बीच होता है। अधिक स्टॉक के लिए अक्सर

बैंकों और एनबीएफसी से डीलरों की फंडिंग में सावधानी बरतने का करेगा अनुरोध

कर्ज के जरिये रकम का इंतजाम किया जाता है, जिसका बोझ उनको वित्तीय परेशानियों को ओर बढ़ा रहा है। बिना बिके वाहनों के स्टॉक में हर 10 दिन की बढ़ोतरी का मतलब है ब्याज लागत में वृद्धि जिससे मार्जिन लगभग दो प्रतिशत तक कम हो सकता है। सिंघानिया ने बताया कि अगर हमारे मार्जिन के दो महीने ब्याज चुकाने में चला जाएगा तो डीलरों के लिए यह भारी बोझ बन जाएगा। आगामी त्योहारी सीजन में हालांकि

बिक्री में इजाफे की उम्मीद है लेकिन अगर डीलर बढ़ती मांग की आस में ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं, तो बिना बिके वाहनों की समस्या और भी बढ़ सकती है। फाडा को डर है कि अगर त्योहार के बाद स्टॉक का स्तर कम नहीं हुआ तो डीलरों को गंभीर नकदी संकट का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें काम बंद करना पड़ सकता है।

फाडा की यह चिंता यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में गिरावट के कारण है जो अगस्त में पिछले साल की तुलना में 4.53 प्रतिशत तक कम हुई और अगस्त 2023 के 3,23,720 के मुकाबले 3,09,053 वाहन रह गई है। इस गिरावट के लिए सुस्त उपभोक्ता मांग, अत्यधिक बारिश के कारण फंडिंग हालात और पिछले बिना बिके वाहनों की 'चिंताजनक' स्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले महीने की तुलना में बिक्री में 3.46 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

अनबिके वाहनों का संख्या बढ़ने की वजह से फाडा ने चेतावनी दी है कि अगर त्योहारी सीजन के बाद इसमें कमी नहीं आती है तो हालात और खराब हो सकते हैं क्योंकि डीलरों को साल के आखिर में सेल के दबाव और अतिरिक्त छूट देनी पड़ती है। इससे पहले से ही कम लाभ मार्जिन पर और दबाव बन सकता है जिससे देश भर में डीलरशिप की वित्तीय व्यावहारिकता खतरे में पड़ सकती है।

फैब टूल कंपनियों की नजर भारतीय बाजार पर

शाइन जैकब चेन्नई, 8 सितंबर

विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में कोई भी फैब संयंत्र चार प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं - एप्लाइड मैटेरियल्स, एएसएमएल, केएलए और टोक्यो इलेक्ट्रॉन - के उपकरणों के बिना काम नहीं कर सकता। भारत में और अधिक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की योजना बनने की वजह से प्रमुख टूल विनिर्माता भी अपनी नजरें देश पर जमाए हुए हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फैब टूल विनिर्माता और 26.52 अरब डॉलर के वार्षिक राजस्व वाली एप्लाइड मैटेरियल्स भारत में विनिर्माण इकाई लगाने की योजना बना रही है। अगर सूत्रों पर यकीन करें तो कंपनी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए तमिलनाडु पर ध्यान केंद्रित किया है। इसे चीन-प्लस-वन रणनीति भी माना जा

रहा है क्योंकि कंपनी ने हाल में अग्रणी सेमीकंडक्टर उपकरण विनिर्माता के रूप में अपना शीर्ष स्थान गंवा दिया है। डच कंपनी एएसएमएल ने उसकी जगह ले ली है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद एप्लाइड मैटेरियल्स अपनी 43 प्रतिशत बिक्री के लिए चीन पर निर्भर है। कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर विनिर्माताओं में से एक है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब एप्लाइड मैटेरियल्स चेन्नई के तारामणी में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और उपकरणों के लिए उन्नत एआई युक्त प्रौद्योगिकी विकास केंद्र लगाने की योजना बना रही है। इससे 500 नौकरियां पैदा होंगी। यह साफ नहीं है कि कंपनी भारत में अपने प्रमुख फैब टूल विनिर्माण पर ध्यान देगी या सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर।

वैश्विक स्तर की दिग्गज कंपनी एप्लाइड मैटेरियल्स कर रही विनिर्माण इकाई पर विचार

घटनाक्रम के जानकार उद्योग के एक सूत्र ने कहा, 'वह भारत में लंबे समय तक काम करने पर विचार कर रही है। तमिलनाडु का यह केंद्र उसकी शुरुआत हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अपने नए प्रोत्साहन शुरू किए जाने के बाद वह (कंपनी) विनिर्माण में प्रवेश कर सकती है।' कैलिफोर्निया की इस कंपनी ने बिजनेस स्टैंडर्ड के इन सवालों का जवाब नहीं दिया कि क्या उसने भारत में विनिर्माण के लिए चेन्नई को चुना है।

अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत में पांच सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दे चुका है। इसमें गुजरात में 2.75 अरब डॉलर के निवेश

के साथ अमेरिकी कंपनी माइक्रोन की एटीएमपी (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग) इकाई और ताइवान की पॉवरचिप सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन (पीएसएमसी) के साथ साझेदारी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) द्वारा धोलेरा (गुजरात) में देश की पहली सेमीकंडक्टर फैब इकाई शामिल है। अन्य तीन इकाइयां हैं - मोरियांग (असम) में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीटी), साणंद (गुजरात) में सीजी पावर की इकाई (जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी में) तथा साणंद में केनेस सेमीकॉन की इकाई। एप्लाइड मैटेरियल्स कथित तौर पर नए बाजारों की तलाश कर रही है क्योंकि चीन ने अपनी खुद की चिप आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति तैयार की है।

टाटा के वित्तीय सेवा कारोबार में भारी मुनाफा

टाटा समूह के गैर-सूचीबद्ध वित्तीय सेवा कारोबारों में इस वर्ष भारी मुनाफा दर्ज किया गया है। समूह के वित्तीय सेवा कारोबार टाटा कैपिटल ने 13,309 करोड़ रुपये के राजस्व पर 2,492 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए टाटा संस की वार्षिक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। बीमा क्षेत्र के दो संयुक्त उपक्रमों

में-टाटा एआईए जनरल इश्योरेंस ने 685 करोड़ रुपये और टाटा एआईए लाइफ इश्योरेंस ने 1,313.84 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया है। सामान्य बीमा कंपनी में टाटा संस के पास 74 प्रतिशत और जीवन बीमा कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सामान्य बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 15,422.56 करोड़ रुपये का कुल कारोबार दर्ज किया है, जबकि जीवन बीमा संयुक्त उद्यम में 25,691 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा टाटा कैपिटल को एनबीएफसी की ऊपरी स्तर वाली कंपनी के रूप में वर्गीकृत करने के बाद टाटा समूह फिलहाल कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रहा है।

सिनेपोलिस को अखरी मॉल की कमी

रोशनी शोखर मुंबई, 8 सितंबर

भारत में मॉल की संख्या कम बढ़ने के कारण मेक्सिको की अंतरराष्ट्रीय मूवी थियेटर श्रृंखला सिनेपोलिस की भारतीय इकाई की बढोतरी पर अटक डाला है। देश की पहली अंतरराष्ट्रीय सिनेमा प्रदर्शक सिनेपोलिस ने 2009 में भारत में आई थी। उसका लक्ष्य 10 वर्षों में 1,000 स्क्रीन हासिल करना था। इस साल सिनेपोलिस की योजना 280 करोड़ रुपये की क्षमता विस्तार के साथ देश भर में 80 स्क्रीन शुरू करने की थी। इसके लिए रकम अंतरिक तौर पर जुटाई गई थी। उन 80 स्क्रीनों में से सिनेपोलिस इंडिया ने 50 स्क्रीनों के लिए फिट आउट प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सिनेपोलिस इंडिया के प्रबंध निदेशक देवांग संपत ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बतवाते हुए कहा, 'अब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि हम 1,000 स्क्रीन शुरू करना चाहते थे मगर यह आसान नहीं था। फिलहाल हमारे पास 450 स्क्रीन हैं।' उन्होंने कहा, 'सिनेमा पूरी तरह से मॉल पर निर्भर होते हैं और कई स्क्रीन शुरू करने के लिए हमें उतने मॉल नहीं दिखते हैं। इसलिए फिलहाल हम उन 80 स्क्रीनों पर ही ध्यान जारी रखेंगे। हम एक साल में 40 या 50 स्क्रीन शुरू करने में सक्षम हो सकते हैं।' संपत ने कहा कि अगर लाइसेंस समय पर मिल जाए और लिडर भी तय वक्त पर मॉल तैयार कर दें तो सिनेपोलिस अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। 2024 में सिनेपोलिस लक्ष्य 10 वर्षों में कुछ परिचालन परियोजनाओं के साथ हैदराबाद में 11, जयपुर में, गुस्साम में 1 और दिल्ली में 1 स्क्रीन शुरू किया है। सिनेमा ऑपरेटर के लिए महानगर, बड़े शहरों और मझोले शहरों में ही विस्तार करना मानदंड नहीं है। उन्होंने कहा, 'बड़ी तस्वीर है कि जब अब परिपक्व बाजारों से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि भारत में अभी भी काफी हद तक थियेटर्स की संख्या कम है।' भारत अभी भी विकासशील है और हर इलाके में फिल्म देखने की स्थिति एक जैसी नहीं होगी। सिनेपोलिस इंडिया के सिनेमा कारोबार में वृद्धि देखी जा रही है और वैश्विक महामारी के पहले के स्तर के मुकाबले अब कुल दर्शकों की संख्या में भी 15 फीसदी का इजाफा होने की उम्मीद है।

नए सौदों की तैयारी में ऐपल

पृष्ठ 1 का शेष

टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने होसुर कारखाने में आईफोन के पुर्जे बनाना शुरू किया। टाटा ने आईफोन के वेंडर विस्ट्रॉन के अधिग्रहण के साथ ही आईफोन असेंबलिंग में भी दस्तक दी है। अब तमिलनाडु में पेगार्टॉन के असेंबली कारखाने को खरीदने के लिए भी बातचीत चल रही है।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स होसुर में अपना चौथा कारखाना स्थापित करने पर 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। उसमें आईफोन को असेंबल किया जाएगा और वहां उत्पादन इसी साल जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 में भारत में आईफोन का उत्पादन 14 अरब डॉलर का हो गया और इसमें से 10 अरब डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया गया। ऐपल अपने वेंडरों के साथ पीएलआई के लिए पात्रता हासिल करना चाहती है क्योंकि आईफोन के 10 फीसदी उत्पादन को चीन से भारत स्थानांतरित करने की उसकी योजना है। हालांकि उसने इस लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 में पीएलआई योजना के अंत तक यह आंकड़ा 20 से 25 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

Usher in competition between EPF and NPS



TRUTH BE TOLD

HARSH ROONGTA

Let's begin with my favourite episode from the 1980s British satire series *Yes Minister*, featuring senior bureaucrat Sir Humphrey and his boss, Cabinet minister Jim Hacker. In a famous scene, Sir Humphrey justifies the existence of a hospital with no patients but 500 administrative staff:

Jim Hacker: "A hospital without patients? What's the point of that?"

Sir Humphrey: "It's a perfectly good hospital, Minister. It has excellent administration and an efficient staff."

Jim Hacker: "But no patients?"

Sir Humphrey: "Patients are an unnecessary inconvenience for the staff."

Jim Hacker: "Isn't the purpose of a hospital to have patients?"

Sir Humphrey: "Oh no, Minister. The purpose of the health service is to provide health care, not health."

This dialogue perfectly satirises the absurdity of outdated systems, reminding me of rules in our formal sector, framed in the 1950s. These rules on Employee Provident Fund (EPF), Employees State Insurance (ESI) and Profession tax burden employers and employees alike, especially as we struggle to increase formal employment.

Take the example of Sarita, a (fictitious) new employee in Mumbai earning ₹15,000 per month (₹1.80 lakh annually). She must pay a profession tax of

₹2,500 annually. The administrative burden of paying this tax is high. With no time limit for arrears collection, notices can arrive 10-15 years later, with steep penalties.

Next, Sarita (₹1,350) and her employer (₹5,850) must pay a total of ₹7,200 annually to the Employees' State Insurance Corporation (ESIC). However, getting claims from ESIC is notoriously difficult, effectively making it another tax. ESIC holds ₹1,70,000 crore in reserves. The claims paid (₹14,000 crore) are 83 per cent of contributions (₹17,000 crore), and investment income (₹7,000 crore) is 41 per cent of contributions (Source: Accounts for year ended March 31, 2023). The numbers reveal a system where contributors have long given up hope of receiving claims.

Then you have the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) triplets. Sarita contributes ₹1,800 monthly to her EPF, while her employer contributes ₹600 to her account, plus ₹75 in administrative charges. In addition, her employer contributes ₹1,200 to her Employees' Pension Scheme (EPS) account and ₹900 for her life insurance (of ₹7 lakh), under the Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) scheme.

All these small deductions add up. Sarita pays ₹25,450 per year (₹21,600 EPF + ₹2,500 profession tax + ₹1,350 ESIC), leaving her with ₹1,54,550 from her salary of ₹1,80,000. Meanwhile, her employer pays a total of ₹39,250 (₹7,200 EPF, ₹24,400 EPS, ₹900 EDLI, ₹900 administrative charges and ₹5,850 ESI), making Sarita's total cost to the employer ₹2,19,250. The difference (₹64,700) between her employer's cost and Sarita's

take-home pay is 42 per cent—coincidentally the same tax rate for individuals earning over ₹5 crore annually. Effectively, the lowest-paid employees are taxed at the same rate as the highest earners.

The benefits are illusory. After March 31, 2023, subscribers withdrawing money from EPF do so based on estimated earnings. EPFO has 5 lakh dormant accounts, and its infrastructure is crumbling, leading to delayed payments, according to reports. EPF must be the highest-cost fund manager globally, with zero accountability. Its pension scheme, according to the last valuation in 2019, revealed a ₹37,000 crore deficit, which has likely grown since.

Any deficit in the EDLI scheme remains undisclosed in the annual accounts. Former finance minister Arun Jaitley remarked in his 2015-16 Budget speech, "Both EPF and ESI have hostages, rather than clients. Further,

the low-paid worker suffers deductions greater than the better-paid workers, in percentage terms." Yet, EPFO has stonewalled the interoperability between the National Pension System (NPS) and EPF for the past nine years.

Truth be told, the government must stop listening to the Indian Sir Humphreys advocating for the status quo at EPFO and ESIC. To create formal jobs, competition needs to be introduced for both EPFO (with NPS) and ESIC (with health insurance companies). Contributions should also be voluntary for low-paid workers. We need to stop levying a 42 per cent "tax" on our lowest-paid employees.

The writer heads Fee-Only Investment Advisors LLP, a SEBI-registered investment advisor; X (formerly Twitter): @harshroongta

Blind bets on IPOs can be risky if market sentiment changes

If the company's quality is sound but valuation is high, wait for a correction

SANJAY KUMAR SINGH & KARTHIK JEROME

Individual investors sold over 50 per cent of the shares (by value) allotted to them in initial public offerings (IPOs) within a week of listing, and 70 per cent within a year, according to a study by the Securities and Exchange Board of India (Sebi). The study compiled data from 144 IPOs listed between April 2021 and December 2023.

Lure of quick gains

Experts attribute the short-term approach adopted by retail investors to several factors. Most investors lack the necessary skills, nor do they dedicate the time and effort required to analyse each IPO thoroughly. "Since investors lack conviction in the IPOs they invest in, they are unable to hold on to them for the long term," says Deepak Jasani, head of retail research, HDFC Securities.

He cites a couple more reasons for early exits. "Most IPOs are offered at high valuations. After listing, many fall in value, so investors exit early to avoid possible losses," he says.

In bullish market conditions, a large percentage of IPOs provide listing gains. "Most retail investors do not understand the fundamentals of the company, nor read the red herring prospectus. They simply bet on the likelihood of listing gains in a bullish market," says Ankur Kapur, head of investment, Plutus Capital.

Many investors also rotate their funds into other IPOs. "The reduced timeline for IPO listings allows investors to quickly assess their positions and reinvest their capital in new opportunities," says Sarveer Singh Virk, co-founder and managing director, Shoonya by Finvasia.

Short-term view enhances risk

PITFALLS TO AVOID IN IPO INVESTING

■ Don't invest based solely on tips from friends or colleagues without doing your research

■ Avoid getting influenced by market trends or excitement surrounding a popular IPO

■ Be cautious about companies that are not yet profitable, as it can take a long time for them to show a profit

■ If you are unsure about the company's valuation, don't feel pressured to invest during the IPO phase; wait for a price correction to offer a better entry point after the IPO listing



Short-term bets on IPOs carry several risks. "There is no guarantee every IPO will open at a premium. Sentiment and narrative can turn at any point and an IPO can list at a discount, causing losses," says Kapur.

Short-term bets also carry an opportunity cost. "If the stock becomes a multi-bagger in a few years, investors miss out on its appreciation over the long term," says Jasani.

He further points out that selling a stock in less than a year results in a higher 20 per cent tax on short-term capital gains.

Enter with adequate horizon

Seasoned and confident investors should hold their investments in IPOs for the long term, according to Virk.

Kapur suggests that as with other equity investments, one should invest in an IPO with a minimum three-year horizon, though five years or more is ideal. "Only with such a horizon can you expect meaningful returns," he says.

IPOs: Riskier than already-listed stocks

IPOs inherently carry more risks than stocks that have been listed on the exchanges for some time. "These are new and untested companies. For stocks that have been listed for

some time, historical data is available on management performance and corporate governance. Analysts also have an insight into whether management meets its earnings guidance. That history is not available for the management of IPOs," says Jasani.

Companies typically launch IPOs when their recent performance appears strong. "If the company is facing difficulties, it will not disclose them. Moreover, investors may enter at the peak of the company's business cycle, after which things may go downhill," says Jasani.

Unlike established companies, IPOs lack a comprehensive track record of financial performance. Investors have to rely on the limited data provided in the prospectus. "This makes it challenging to assess the company's profitability, stability, and growth potential," says Virk.

Another challenge is the information asymmetry in IPO investing. Promoters and early institutional investors sell and exit their holdings, partially or fully. Retail investors buy from them. "The seller is better informed and stronger, while the buyer is uninformed and weaker," says Kapur.

IPOs are usually offered at high valuations, allowing promoters to maximise their returns. These high valuations reduce the likelihood of

retail investors making profits, even over the long term.

Conduct due diligence

Retail investors should carefully assess why the company is raising funds through an IPO. If the funds are intended for business expansion, research and development, marketing, or paying off debts, the purpose can be considered reasonable. "An IPO that primarily provides liquidity to early investors, such as through an offer for sale (OFS), could be a red flag," says Virk.

Investors should thoroughly review the prospectus to understand how the company generates revenue and profits. They should evaluate its market position, competitive advantages, and growth potential. "Identifying key competitors and assessing the company's market share, strengths and weaknesses relative to them is crucial," says Virk.

Wait for the right valuation

Once a company has been listed for three months to one year, its reality begins to emerge. "Even if it is a high-quality business, there is a good chance you could buy the stock at a lower valuation six to 12 months later, once the euphoria around its listing has faded. A market downturn may also provide a better entry price," says Kapur.

BHARAT GLASS TUBE LIMITED
CIN: U26109MH1983PLC172146
Registered Office: Shop 1, Shivam, Shivram Nagar, Jail Road, Nashik Road, Nashik - 422101
E-mail id: bggtamd@gmail.com (M)- 7878097670

NOTICE
Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of Bharat Glass Tube Limited will be held on Monday, 30th September, 2024 at 2 P.M. through video conferencing (VC) / other audio visual means (OAVM) in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and pursuant to the General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May 2020 and 9/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and all other relevant circulars issued from time to time, (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM without physical presence of members at a common venue. In compliance with above mentioned Circulars, Notice of AGM and Annual Report of the Company have been sent. The same are also available on the Company's website at www.bharatglass.in and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Instructions for E-voting:
The Company has provided its members remote e-voting facility in compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and relevant rules made thereunder. The Company has engaged NSDL as the authorized agency to provide e-voting facility to its all members.

The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is Monday, 23 September, 2024. The remote e-voting facility shall be open for three (3) days, commencing on Friday, 27 September, 2024 (10.00 am) to Sunday, 29 September, 2024 (5.00 PM) for all the members. A person whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the general meeting. Remote e-voting facility shall not be allowed beyond the said date and time. The members, who attend AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through voting facility during the AGM.

The members may participate in the meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the meeting. Detailed instruction for remote e-voting facility and voting during the AGM are forming part of the Notice of AGM.

Any person who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may cast their votes by following the instructions and process of e-voting as provided in the Notice of AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or 022-48867000 and 022-24997000 or send a request Ms. Pallavi Mhatre Senior Manager, NSDL, Address: Trade World, Awing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 at e-mail id: evoting@nsdl.co.in

For Bharat Glass Tube Limited
Laxmikant Khemka
Director
DIN: 00189218

Date: September 08, 2024
Place: Ahmedabad

XTGLOBAL
XTGLOBAL INFOTECH LIMITED
CIN: L72200TG1986PLC006644
Regd. Office: Plot No.31P&32, 3rd Floor, Tower A, Ramky Selenium, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, TG
Website: www.xtglobal.com; Email ID: company.secretary@xtglobal.com;

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of XTGlobal Infotech Limited ("the Company") will be held on Monday, 30th September, 2024 at 10:00 AM IST ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM, without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on time to time, to transact the business as set out in the Notice calling the AGM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2023-24 is being sent by email to those shareholders holding shares as on 30th August 2024 and whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("RTA")/ Depositories. Members may note that the Notice of the 36th AGM and Annual Report for FY 2023-24 will also be made available on the Company's website at www.xtglobal.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the instructions detailed in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the meeting.

Members, please note that the remote e-voting period shall commence on Thursday, 26th September 2024 (9:00 A.M. IST) and shall end on Sunday, 29th September 2024 (5:00 P.M. IST). The members who could not cast their vote by remote e-voting may also be able to cast their votes using an electronic voting system during the AGM. Once the vote on resolutions is cast by the Members, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Manner of registering /updating e-mail address, bank account details, etc.:

1. Shareholders holding shares in physical mode are requested to register/update KYC details such as PAN (Aadhaar linked), Nomination details, Contact details, (address with PIN, mobile number and email address), Bank Account details (bank name, branch name, account number and IFS code) and Specimen Signature with the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), KFin Technologies Limited. The relevant forms prescribed by SEBI for furnishing the above details are available on the Company's website at <https://xtglobal.com/investors/shareholders-information/> as well as on RTA's website at <https://iris.kfintech.com>.

2. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update KYC details such as PAN (Aadhaar linked), Nomination details, Contact details (address with PIN, mobile number and email address), bank account details and Specimen Signature with the relevant Depository Participant.

In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the AGM Notice through email but on or before the cut-off date for e-voting i.e., Monday, 23rd September, 2024, or has registered his/her/its e-mail address after dispatch of the AGM Notice, he/she/it may obtain the User ID and Password for the purpose of remote e-voting or e-voting during the meeting by writing to the RTA mail id einward.ris@kfintech.com or Company mail id at company.secretary@xtglobal.com.

The Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Tuesday 24th September 2024 to Monday 30th September 2024 (both days inclusive) for the purpose of 36th AGM of the Company.

For any clarifications/ queries with respect to the submission of the above-mentioned forms or e-voting shareholders may contact RTA at 1800-3094-001 or by email on einward.ris@kfintech.com or may connect with the Company by writing an email to company.secretary@xtglobal.com at any time before the meeting.

By order of the Board
For XTGlobal Infotech Limited
Sd/-
Sridhar Pentela
Company Secretary & Compliance officer
A55735

Place : Hyderabad
Date : 07-09-2024

CHADHA PAPERS LIMITED
REGD. OFFICE :- CHADHA ESTATE, NAINITAL ROAD, BILASPUR, RAMPUR- 244921, UTTAR PRADESH
CIN: L21012UP1986PLC018178
Ph: 91053-88000 Fax: 0120-4106161
Email: chadhapersltd@gmail.com, Website: www.chadhapers.com

NOTICE OF 34th AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the "Chadha Papers Limited" will be held at the registered office of the Company at Chadha Estate, Nainital Road, Bilaspur, Rampur- 244921, Uttar Pradesh on Monday, 30th September, 2024 at 02:30 p.m. In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Act and Rules") the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013, and Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 have been sent to the shareholders, whose email id is registered with the company/RTA/Depository Participants and whose email id is not registered are requested to update their email address with the company/its RTA, in case of shares held in physical mode by sending the request at chadhapersltd@gmail.com or RTA at admin@skytinerta.com and Depository participants in case of shares held in demat mode.

The company has provided its shareholders remote e-voting facility in compliance with the section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged CDSL as the authorized agency to provide e-voting facility. The details as required pursuant to the Act and rules are as under:

- The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is 23rd September, 2024. The e-voting shall be open for three (3) days, commencing at 09.00 A.M. on Friday 27th September, 2024 and ending at 5.00 P.M. on Sunday on 29th September, 2024. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangements of ballot papers in this regards at the AGM Venue.
- A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting.
- A person, whose name is recorded in the register of members as on cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot papers, person who acquires shares and becomes shareholder of the Company after issue of the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the login-id and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact to Mr. Deepak Rastogi, Company Secretary, email id: chadhapersltd@gmail.com Phone No. - 9690289890 Address Chadha Estate, Nainital Road, Bilaspur, Rampur- 244921, (U.P).
- The Company has appointed Mr. Sachin Mavi, Company Secretary in Practice, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in Notice of the Annual General Meeting. In case of queries or issues pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact to Mr. Deepak Rastogi, Company Secretary, email id: chadhapersltd@gmail.com Phone No. - 9690289890 Address Chadha Estate, Nainital Road, Bilaspur, Rampur- 244921, (U.P).

The notice of AGM is available on the company's Website chadhapers.com and CDSL website <https://www.evotingindia.com>

Further in terms of Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015 and section 91 of the Companies Act 2013 and applicable rules thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 34th AGM to be held on Monday, 30th September, 2024.

By the order of the Board
For Chadha Papers Limited
Sd/-
Amanbir Singh Sethi
(Whole Time Director)
DIN:-01015203
Address: CTC061 The Crest Park Drive, DLF5, Gurugram, Haryana-122011

Date: 07.09.2024
Place: New Delhi

Markets, Insight Out

Markets, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

